झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (शिकायत) 10/2022– 419

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 28.04.2022

विषयः– राज्य के स्कूली बच्चो को कुकिंग कॉस्ट की राशि अबतक नहीं मिलने संबंधी प्रकाशित समाचार पर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक–06.04.2022 को राज्य के स्कूली बच्चो को वित्तीय वर्ष–2021–22 का मिड डे मील के तहत् मिलने वाला कुकिंग कॉस्ट की राशि अबतक नहीं मिल पाने से संबंधित समाचार प्रकाशित हुई है।

अतः उक्त प्रकाशित समाचार के कतरन की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए करते हुए निदेशानुसार अनुरोध है कि उक्त मामले में यथाशीघ्र कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

20/4/22

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

अनु0–यथोक्त।

Date- 06/04/22

हिन्दुस्तान

एमडीएम | **टेंडर और डीबीटी के नाम पर फंसा पेच, 10 माह के 206 दिन का 395 करोड़ कुकिंग कॉस्ट बच्चों को करना है भुगतान**

वित्तीय वर्ष खत्म, अबतक नहीं मिली कुकिंग कॉस्ट की राशि

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो।
झारखंड के स्कूली बच्चों को 2021-22 का मिड डे मील का चावल तो मिला गया, लेकिन कुकिंग कॉस्ट की राशि नहीं मिली है। टेंडर और डीबीटी के माध्यम से राशि जारी करने पर मामला फंसा रहा।

हालांकि मध्याह्न भोजन प्राधिकरण कुकिंग कॉस्ट की राशि की बात कर रहा है, लेकिन राशि न तो स्कूलों में पहुंची है और ही बच्चों के खाते में। अभी भी 2020-21 वित्तीय वर्ष की राशि ही बच्चों के खाते में दी जा रही है। यह प्रक्रिया पिछले तीन माह से चल रही है, लेकिन अबतक पूरी नहीं हो सकी है।

झारखंड के स्कूली बच्चों को अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक के लिए 206 दिनों तक मिड डे मील का चावल उपलब्ध कराया गया है। हर दिन की कुकिंग कॉस्ट की राशि के आधार पर इस मद में 395 करोड़ रुपये बच्चों को देना है। पहली से पांचवीं के बच्चों को हर दिन 4.95 रुपये कुकिंग कॉस्ट की दर से कुल 1020 रुपये मिलेंगे, जबकि छठी से आठवीं के बच्चों को 7.45 रुपये की कुकिंग कॉस्ट की दर से 1535 रुपये का भुगतान होगा।

प्राइमरी स्कूलों में करीब 20 लाख बच्चे नामांकित हैं, वहीं छठी से आठवीं क्लास में 12 लाख बच्चे नामांकित हैं। इन बच्चों को ही मध्याह्न भोजन योजना का लाभ दिया जाता है। चार फरवरी से 17 जिलों में स्कूल खुल गए थे, जबकि सात जिलों में सात मार्च से स्कूल खुलें हैं। ऐसे में इन सात जिलों में एक महीने के कुकिंग कॉस्ट की राशि बच्चों को दी जाएगी। इससे छह-सात करोड़ रुपये अतिरिका लगेंगे।

पिछली राशि का जारी है भुगतान

जनवरी में ही राज्य सरकार ने अक्तूर 2020 से मार्च 2021 तक के 134 दिनों के लिए कुकिंग कॉस्ट की राशि जारी की थी। राशि बच्चों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जारी की जानी थी, लेकिन बच्चों का बैंक खाता नहीं होने की वजह से राशि बच्चों तक नहीं मिल रही थी। शिक्षा विभाग ने पहले बच्चों का खाता खुलवाने, अभिभावकों के खाते में राशि देने से लेकर बच्चों को नकद राशि का भुगतान करने तक का निर्देश दिया, लेकिन अभी भी सभी बच्चों को राशि नहीं मिल सकी है।

बच्चों का नहीं है खाता, होगी समस्या

शिक्षा विभाग स्कूली बच्चों के बैंक खाते में राशि देने की बात कर रहा है, लेकिन जब सभी बच्चों का बैंक खाता ही नहीं है तो कैसे राशि दी जा सकेगी। जिन बच्चों का बैंक खाता नहीं है उनके अभिभावकों या फिर बच्चों को नकद राशि भुगतान किए जाने की आवश्यकता होगी। विभागीय अधिकारियों की माने तो 19 जिलों में 90 फीसदी से ज्यादा 2020-21 की राशि का भुगतान हो चुका है, जबकि पांच जिलों में यह आंकड़ा 75 फीसदी के करीब है। शिक्षा विभाग जिलों को सभी बच्चों का बैंक खाता खुलवाने का निर्देश दे रहा है।

पहली से पांचवी

पहली से पांचवी में बच्चे : करीब 20 लाख	
कुकिंग कॉस्ट की कुल राशि	204 करोड़
कुकिंग कॉस्ट में प्रति बच्चे तय है	4.95 रुपये
एक बच्चे को 206 दिन के मिलेंगे	1020

छठी से आठवीं

छठी से आठवीं में बच्चे : करीब 12 लाख	
कुकिंग कॉस्ट की कुल राशि	185 करोड़
कुकिंग कॉस्ट में प्रति बच्चे तय है	7.45 रुपये
एक बच्चे को 206 दिन के मिलेंगे	1535 रुपये